



सुविचार

जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं, जब तक हमें वो काम नामुमकिन ही लगता है।

# प्रभात मन्त्र

तजा खबरों के लिए टेली

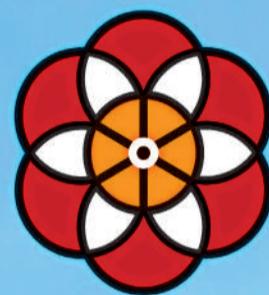
prabhatmantra.com

पृष्ठ 12 | मूल्य 4 रुपये

शुक्रवार  
12.05.2023  
RNI No. - JAHIN/2014/59110

पोस्टल रजिस्ट्रेशन : आरएन /257/2021-23

## कैंसर सेवाओं में आशाओं से भरा नया दौर



**RANCHI  
CANCER HOSPITAL &  
RESEARCH CENTRE**

उद्घाटन  
**श्री हेमंत सोरेन**  
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार  
द्वारा

12 मई, 2023



आरसीएचआरसी में हम प्रदान करते हैं |



किफायती  
कैंसर उपचार



अत्याधुनिक  
तकनीक



विश्वस्तरीय  
नैदानिक सुविधाएँ



पैलिएटिव केयर



अनुभवी और संवेदनशील  
डॉक्टर्स और नर्सेस





जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं, जब तक हमें वो काम नामुखिकन ही लगता है।



# प्रभात मन्त्र

शुक्रवार

12.05.2023

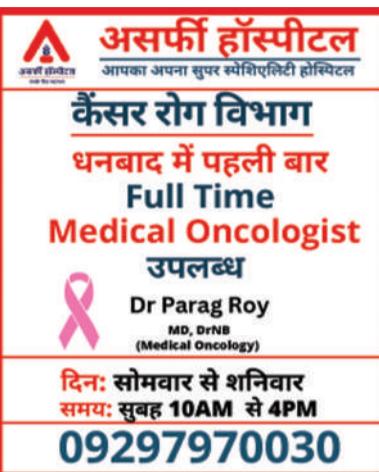
RNI No. - JAHIN/2014/59110

तजा खबरों के लिए टेली

prabhatmantra.com

पृष्ठ 12 | मूल्य 4 रुपये

पोस्टल रजिस्ट्रेशन : आरएन /257/2021-23



रांची का तापमान

अधिकतम 30°  
न्यूनतम 18°

विषय न्यूज़

पश्चिमी सिंहभूमः आईईडी विस्फोट में जवान घायल

पश्चिमी सिंहभूमः पश्चिमी सिंहभूम चाँदबासा जिले के गोइलकरा थाना क्षेत्र के इच्छातृ जंगल में गुरुवार को आईईडी विस्फोट होने से सीआरपीएफ 60 वीं बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गोइलकरा थाना क्षेत्र के इच्छातृ जंगल में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में सर्व अधियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान जवान जमीन में ल्हांठ आईईडी की चेपेट में आ गया। आईईडी विस्फोट होने से सीआरपीएफ के जवान शेषमणि गंभीर रूप से घायल हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका व महाराष्ट्र में साल भर पहले हुए सियासी उठापटक पर दिया बड़ा फैसला, कहा

गवर्नर को उद्धव से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत फैसला था



## प्रशासन पर रहेगा सरकार का नियंत्रण

एजेंसी

नई दिल्ली : केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राशीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियन्त्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बांध जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली धंपच सदस्योंगत सर्विकान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सर्वसम्मति का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी दी कि जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर राशीय राजधानी की बाकी प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण है। उपराज्यपाल इन तीन मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्विकान पीठ ने इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और 2019 के जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से असहमति जताई। 2019 के फैसले में कहा गया था कि तभाम

### सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल गदगद

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने द्राष्टव्यप्र प्रोटिटिंग के अधिकारों को दिल्ली सरकार के अधीन करने का जो फैसला सुनाया है उसके बाद अग्र आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को नई संजीवी निवारण हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल सरकार और मंजूब हो गई है। इस फैसले के आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्विकान पीठ से फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सियासी उठापटक पर दिया बड़ा फैसला, कहा



### सुप्रीम कोर्ट के फैसले से घटा दिल्ली के उपराज्यपाल का कद

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट का वे आयह फैसला दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण और अधिकार से जुड़ा है। इसे लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विवादातार की थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मुकाबो हुए साफ कर दिया ति दिल्ली की पुलिस, जीवीन और पलिक ऑर्डर पर कोट का अधिकार है, तो किंव बाली सभी मामलों पर हुनी हुई सरकार का ही अधिकार होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक तरह से उपराज्यपाल का कद भी घट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि पुलिस, जीवीन और पलिक ऑर्डर को छोड़कर बाली सभी दूसरे मामलों पर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सहाय माननी लीजी।

नहीं है, नहीं तो वो आज इसीफा दे देती।' इस पर डिटी सीपी देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि उद्धव ने नैतिकता नहीं बल्कि हार की डर के चलते इसीफा दिया। मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए। जून 2022 में एकनाथ शिंदे गुट की बागत के बाद महाराष्ट्र विकास अधारी गठबंधन सरकार गढ़ गई थी। 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस मामले में दोनों गुटों की तरफ से 6 वाचिकार दावर की गई थीं। उद्धव ठाकरे और सरकार को बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र विकास अधारी सरकार बहाल नहीं की जा सकती है। ब्योकि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में फैसला देस्ट के लिए कहना गलत फैसला था। गवर्नर के पास बहुमत पर शक करने का ठोस आधार नहीं था। अपने से तो जब चुनाव बंद कर दिया या उहोंने मतियों के निर्देश नहीं माने तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर असर पड़े।

## नेक इदादा निभा द्ये वादा

## नियुक्ति लगातार...



अंतर्गत नियुक्त सहायक लोक अभियोजकों को  
हार्दिक शुभकाग्नारं और जीर्ण



















